- **जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा** : आरटीआई लागू होने के बाद से भारत में 25 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। गवाहों को संरक्षण प्रदान करने के मामले में बहुत अधिक विश्वसनीय विकास नहीं हुआ है।

3. प्रशासनिक मुद्दे :

- राज्य तंत्र के काम में **संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जबाबदेही का अभाव,** जहां नौकरशाही अभी भी गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास करती है, सुभेद्य/कमजोर वर्गों के प्रति लापरवाही आदि।
- जहां आम लोगों और प्रशासन के बीच सीधा सम्पर्क होता है वहां नौकरशाही में लेट लतीफी अभी भी आम बात है। जबकि दूसरी ओर सरकार व्यवसायियों को आमंत्रित कर रही है।
- उन परिवर्तनों का प्रतिरोध करना जो पारदर्शिता और जबाबदेहियों को बढ़ावा देते हैं । जैसे प्रौद्योगिकी को कम अपनाना, सूचनाओं का कोई स्वैच्छिक प्रकटीकरण नहीं, नए कौशल सीखना।
- **भ्रष्टाचार :** हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार बैरोमीटर नामक अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें यह कहा गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे भ्रष्ट देश भारत है।

4. आर्थिक मुद्दे :

- **अर्थव्यवस्था का घटिया प्रबंधन** जैसे संरचनात्मक समस्याओं के कारण मंदी, कृषि में गतिहीनता/स्थिरता, विनिर्माण क्षमता का कम उपयोग आदि।
- जहां राजकोषीय फिसलन एक आम घटना बन चुकी हो वहां राजकोषीय असंतुलन जारी रहता है । सरकार हमेशा एफआरबीएम अधिनियम के तहत स्थापित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही है। अस्थायी और प्रतिक्रियाशील निर्यात-आयात नीतियों के परिणामस्वरूप उच्च चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह लगातार हो रहा है।
- अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर में क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है। उदाहरण - हरित क्रांति ने उत्तरी राज्यों को लाभान्वित किया लेकिन पूर्वी राज्य अभी भी गुजर-बसर कृषि पर निर्भर हैं। जहां पश्चिमी और दक्षिणी भारत विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का केंद्र है। वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य अभी भी अविकसित हैं।

5. सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे :

- कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी सेवाओं से अभी भी वंचित है। उदाहरण: शांता कुमार समिति के अनुसार, लाभार्थियों का 66% अपवर्जन त्रुटि है, केवल 33% किसानों को ही एमएसपी के तहत लाभ मिल पाता है।
- सामाजिक, धार्मिक, जाति और लिंग संबद्धता के आधार पर लोगों को हाशिए पर रखा जाता है तथा उनका बहिष्करण किया जाता है। जनजातीय लोग पर अपने दूरस्थ आवासों के कारण हमेशा बहिष्करण का खतरा बना रहता है।
- बड़ी संख्या में मूक/बेजुबां गरीबों बहुत कम अवसरों के साथ शासन में भागीदार है।
- भौतिक पर्यावरण की स्थिति का खराब होना, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। उदाहरण- शहरी द्वीपों का हिटिंग, ठोस अपशिष्टों को ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाना, नदियों और आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण आदि।

सुशासन :

- शासन स्वयं एक तटस्थ शब्द है जबकि **"सुशासन"** का तात्पर्य सकारात्मक गुणों और शासन की गुणवत्ता से जुड़े मूल्य हैं। सुशासन एक गतिशील अवधारणा है और सुशासन के पहलुओं को परिभाषित करने में बहुत अधिक मनोवाद की आवश्यकता होतीहै।